(ग) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के आरंभ होने के समय मौजूदा सभी प्राथमिक स्कूलों को 31 मार्च, 1995 तक पठन-पाठन उपस्कर संस्वीकृत किए गए हैं। अतिरिक्त शिक्षकों के 98% पद संस्वीकृत किए गए है तथा 55% अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण किया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) जिन प्राथमिक स्कूलों में नामांकन 100 से अधिक है, उनमें तीसरा शिक्षक प्रदान करने की योजना के क्षेत्र में विस्तार किया गया है। अब उच्च प्राथमिक स्कूलों को भी पठन-पाठन सामग्री प्रदान की जाएगी। आठवीं योजना के दौरान विस्तृत कार्यक्रम के अंतर्गत, 30% कवरेज की योजना है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के अत्यधिक ऊंचे मूल्य

607. **श्री सोमपाल:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के अत्यधिक ऊंचे मूल्य के बारे में दिनांक 8 जुलाई, 1995 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार को देखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकर इन पुस्तकों के ऐसे ऊंचे मूल्य के कारणों की जांच कराने का विचार रखती है;

(ग) क्या यह सच है कि परिषद में सस्ते मूल्य के कागजों के उपलब्ध होने के बावजूद परिषद के कतिपय अधिकारियों द्वारा बाजार से मंहगे कागजों की खरीद किया जाना इन पुस्तकों के अधिक मूल्य निर्धारित करने का कारण है;

(घ) यदि हां, तो परिषद् के अधिकारियों द्वारा ऐसा करने के क्या कारण हैं और इन अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी हां।

(ख) से (ङ) समाचार पत्र की रिपोर्ट में किया गया उल्लेख राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा कक्षा XII के लिए प्रकाशित भौतिकी खंड की पाठ्य पुस्तक के वर्तमान संस्करण के संदर्भ में है जिसमें पिछले संस्करण की अपेक्षा काफी ज्यादा पृष्ठ हैं और जो बेहतर किस्म के कागज पर मुद्रित हैं जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चित्रों की अधिक स्पष्टता के साथ छपाई की जा सके।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के अनुसार पाठ्य पुस्तक की कीमत न लाभ न हानि की अनुमोदित कीमत निर्धारण पद्धति के अनुसार निर्धारित की गई है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की वित्तीय स्थिति

608. **श्री जनार्दन यादव:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा लाभ दर्शाये जाने के बावजूद इसकी वित्तीय स्थिति बदतर हालत में है;

(ख) यदि हां, तो इसकी इक्विटी पूंजी सुरक्षित पूंजी और अधिशेष के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है और वर्ष 1991-92 से कम्पनी का ऋण-स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में और विनिवेश करने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या कम्पनी की वित्तीय स्थिति के मर्चेन्टनर शेयरों के मूल्यों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है?